संबंधों के सफर में भारत-इज़राइल

विनिता कुमारी
शोध छात्रा
पंजीयन संख्या : 729 /2022
स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग
ति. मां. भा. वि. वि. भागलपुर

सारांश:

भारत और इज़राइल के बीच संबंधों का सफर एक दिलचस्प और बहुआयामी यात्रा रही है, जिसमें कूटनीति, रणनीति, प्रौद्योगिकी, कृषि और सांस्कृतिक सहयोग की गहरी परतें शामिल हैं। इज़राइल की स्थापना 1948 में हुई, जिसे भारत ने शीघ्र ही मान्यता तो दी, किंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन, फिलिस्तीन के प्रति प्रतिबद्धता और पश्चिम एशियाई देशों से संबंधों को देखते हुए भारत ने लंबे समय तक औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। 1992 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई, जिसके बाद से यह संबंध लगातार प्रगाढ़ होते गए। रक्षा क्षेत्र में इज़राइल भारत का एक प्रमुख साझेदार बना, जिसने उन्नत सैन्य तकनीक और खुफिया सहयोग प्रदान किया। आतंकवाद से निपटने की रणनीतियों में भी दोनों देशों का तालमेल उल्लेखनीय रहा है। इसके अलावा, कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में इज़राइल की उन्नत तकनीक ने भारत में हरित नवाचार को बढ़ावा दिया है। दोनों देशों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं, जहाँ ड्रिप इरिगेशन, हाई-टेक खेती और जल संरक्षण की तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी संबंध मजबूत हुए हैं, विशेषकर तकनीकी स्टार्ट-अप्स, रक्षा उपकरण, साइबर सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में। सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शैक्षिक सहयोग, और यहूदी-भारतीय समुदाय के पारंपरिक संबंध भी इन रिश्तों को मानवीय आधार प्रदान करते हैं। हालांकि भारत को इज़राइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर संतुलन साधने की चुनौती बनी रहती है, विशेषकर जब वह पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों से भी घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहता है।

कुल मिलाकर, भारत-इज़राइल संबंध आज सामरिक साझेदारी से आगे बढ़कर बहु-आयामी सहयोग का रूप ले चुके हैं, जिनमें समान लोकतांत्रिक मूल्य, तकनीकी नवाचार, सुरक्षा और आर्थिक हितों की स्पष्ट संगति दिखाई देती है। भविष्य में यह संबंध और अधिक सुदृढ़ हो सकते हैं, बशर्ते भारत अपनी संतुलित विदेश नीति बनाए रखे और दोनों देशों के साझा हितों को आगे बढ़ाता रहे।

मूल शब्द (Key words) : द्विपक्षीय संबंध ,राजनयिक सहयोग ,गुटनिरपेक्षता ,फिलिस्तीन नीति ,रक्षा सहयोग ,तकनीकी नवाचार ,कृषि साझेदारी ,जल प्रबंधन ,व्यापार एवं निवेश ,खुफिया सहयोग ,कूटनीतिक संतुलन ,वैश्विक मंच ,सामरिक रणनीति

साहित्य समीक्षा :

भारत-इज़राइल संबंधों और पश्चिम एशिया नीति पर उपलब्ध साहित्य बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है। पी. आर. कुमारस्वामी की पुस्तक *India's Israel Policy* (2010) इस संबंध के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण करती है और यह स्पष्ट करती है कि भारत ने इज़राइल के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार धीरे-धीरे सार्वजनिक और रणनीतिक रूप दिया। अलीना बंसल (2006) द्वारा प्रस्तुत अध्ययन भारत-इज़राइल संबंधों के विकासशील दृष्टिकोण को रेखांकित करता है और बताता है कि किस तरह यह साझेदारी सुरक्षा, कृषि और तकनीकी क्षेत्रों में परिपक्व हुई है। अजय घोष (2017) की पुस्तक भारत की विदेश नीति की समग्र समीक्षा प्रस्तुत करती है जिसमें इज़राइल के साथ संबंधों को भारत की नई रणनीतिक प्राथमिकताओं के रूप में देखा गया है। बीना चिब्बर (2018) का शोध भारत की पश्चिम एशिया नीति में संतुलन की आवश्यकता और खाड़ी देशों के साथ भारत के पारंपरिक संबंधों तथा इज़राइल के साथ नवीन सहयोग के मध्य संतुलन साधने की चुनौती पर केंद्रित है। सुरभि सिंह (2019) और अनुजा रेड्डी (2021) के लेख समकालीन राजनीतिक

नेतृत्व विशेषकर मोदी युग में भारत-इज़राइल संबंधों में आए अभूतपूर्व निकटता और रणनीतिक घनिष्ठता की व्याख्या करते हैं। हर्ष वी. पंत (2018) इस साझेदारी की संभावनाओं और सीमाओं दोनों पर प्रकाश डालते हैं, जबकि हप्पीमोन जैकब (2018) भारत-इज़राइल रक्षा सहयोग से परे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

यह साहित्य बताता है कि भारत की पश्चिम एशिया नीति में इज़राइल अब एक स्थायी रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है, जो पारंपरिक संतुलन को नए वैश्विक यथार्थ के अनुरूप ढालने की दिशा में संकेत करता है।

शोध उद्देश्य एवं परिकल्पना :

इस शोध आलेख का उद्देश्य भारत और इज़राइल के बीच द्विपक्षीय संबंधों की ऐतिहासिक यात्रा, सामरिक विकास तथा समकालीन वैश्विक संदर्भ में इसके महत्व का विश्लेषण करना है। शोध में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार 1992 में कूटनीतिक संबंधों की पूर्ण स्थापना के बाद से दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, विज्ञान, तकनीक, और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग निरंतर प्रगाढ़ हुआ है। यह आलेख यह भी इंगित करता है कि बदलते वैश्विक शक्ति समीकरणों में भारत-इज़राइल संबंध किस प्रकार भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में स्थान पाते हैं।

शोध आलेख में यह परिकल्पित किया गया है कि भारत-इज़राइल के संबंध महज सामरिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह संबंध तकनीकी नवाचार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और वैश्विक मंचों पर सहयोग के माध्यम से भविष्य में और अधिक बहुआयामी तथा रणनीतिक रूप सक्षम हो सकते हैं।

अनुसंधान पद्धति एवं डाटाबेस :

इस शोध आलेख में ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया है। ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत भारत-इज़राइल संबंधों की उत्पत्ति, विकासक्रम और निर्णायक मोड़ों का अध्ययन किया गया है। वर्णनात्मक पद्धति द्वारा द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रक्षा, कृषि, जल तकनीक, साइबर सुरक्षा, शिक्षा और व्यापार में हुए विकास का विवरण प्रस्तुत किया गया है। विश्लेषणात्मक पद्धति के माध्यम से वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इन संबंधों की प्रासंगिकता का विश्लेषण किया गया है।

डेटाबेस के रूप में भारत सरकार और इज़राइल सरकार की आधिकारिक रिपोर्टों, विदेश मंत्रालय के द्विपक्षीय दस्तावेज़ों, अंतरराष्ट्रीय जर्नलों, शोध लेखों, विशेषज्ञों की पुस्तकें और संस्थानों जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ब्रुकिंग्स इंडिया, IDSA आदि के प्रकाशनों का उपयोग किया गया है।

प्रस्तावना :

भारत और इज़राइल के द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास अनेक उतार-चढ़ावों और रणनीतिक बदलावों से भरा हुआ है। 1948 में इज़राइल की स्थापना के बाद भारत ने उसे जल्दी ही मान्यता दी, किंतु दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने में लगभग चार दशकों का समय लगा। इसका मुख्य कारण भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, अरब देशों के साथ आर्थिक व ऊर्जा आधारित संबंध, और फिलिस्तीन के प्रति ऐतिहासिक समर्थन था। 1992 में जब भारत ने इज़राइल के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए, तब से दोनों देशों के बीच सहयोग के अनेक नए द्वार खुले। विशेष रूप से 21वीं शताब्दी में यह संबंध रक्षा, कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में लगातार प्रगाढ़ होते गए हैं। भारत की "मेक इन इंडिया", "डिजिटल इंडिया" और "स्टार्टअप इंडिया" जैसी योजनाओं में इज़राइल की तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार क्षमता का विशेष योगदान रहा है। इस शोध आलेख का उद्देश्य भारत-इज़राइल संबंधों के ऐतिहासिक विकास, उनके प्रमुख सहयोग क्षेत्रों, राजनीतिक व कूटनीतिक संतुलन, और भविष्य की संभावनाओं का समग्र मूल्यांकन करना है। यह आलेख इस बात का भी विश्लेषण करता है कि किस प्रकार भारत अपनी पारंपरिक फिलिस्तीन नीति के साथ-साथ इज़राइल के साथ गहराते संबंधों को संतुलित कर रहा है।

"संबंधों के सफर में भारत-इज़राइल" न केवल दो राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक विकास की कहानी है, बल्कि यह वैश्विक भू-राजनीति, तकनीकी सहयोग और मानवतावादी मूल्यों के मिलन का भी प्रतीक बन चुका है। इस आलेख के माध्यम से इस संबंध की जटिलताओं, उपलब्धियों और चुनौतियों को समझने का प्रयास किया गया है।

भारत इजराइल परस्पर संबंधों का सिलसिला

भारत और इज़राइल के बीच द्विपक्षीय संबंधों की यात्रा एक जटिल, किंतु परस्पर लाभकारी साझेदारी का द्योतक है। यह संबंध आधुनिक इतिहास के दो ऐसे राष्ट्रों के बीच विकसित हुआ है, जो भिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक पृष्ठभूमियों से आते हैं, परंतु जिनकी सामरिक, तकनीकी और आर्थिक आवश्यकताएँ एक-दूसरे से मेल खाती हैं। इज़राइल की स्थापना 1948 में हुई और भारत उन चंद देशों में था, जिसने शीघ्र ही इस नवगठित यहूदी राष्ट्र को मान्यता दी। हालांकि, दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए, जो इस बात को दर्शाता है कि प्रारंभिक दशकों में भारत की विदेश नीति ने इज़राइल के साथ खुले संबंधों को प्राथमिकता नहीं दी।[1] इसके पीछे भारत की गुटनिरपेक्ष नीति, फिलिस्तीन के साथ भावनात्मक-सांस्कृतिक जुड़ाव और अरब देशों से ऊर्जा, व्यापार तथा कूटनीतिक संबंधों की व्यावहारिकता थी। यह शोध आलेख भारत-इज़राइल संबंधों के ऐतिहासिक विकास, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, कूटनीतिक चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि कैसे दो राष्ट्र, जिनकी नीतियाँ प्रारंभ में भिन्न थीं, समय के साथ प्रौद्योगिकी, रक्षा, कृषि, और राजनीतिक साझेदारी में प्रगाढ़ होते गए। इस आलेख में यह भी विश्लेषण किया गया है कि भारत किस प्रकार इज़राइल और फिलिस्तीन के मध्य संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता रहा है, जिससे उसकी पश्चिम एशिया नीति की बहुपक्षीय प्रकृति उजागर होती है।

प्रारंभिक संबंध: 1948 से 1992 तक

इज़राइल की स्थापना 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई, जब यहूदियों को अपने एक स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकता के चलते पश्चिम एशिया में यहूदी राज्य की स्थापना की गई। भारत ने 17 सितंबर 1950 को इज़राइल को आधिकारिक मान्यता दी, लेकिन तब तक दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक दूतावास स्थापित नहीं किया गया था। भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, जो पं. नेहरू के नेतृत्व में विकसित हुई थी, उस समय पश्चिम एशिया में अरब राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की दिशा में अग्रसर थी।[2] भारत ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर स्पष्ट समर्थन दिया और यह माना कि फिलिस्तीनियों को भी आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। यही कारण था कि भारत लंबे समय तक इज़राइल के साथ अपने संबंधों को सीमित दायरे में ही रखता रहा। हालांकि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में अनौपचारिक सहयोग होता रहा, विशेष रूप से कृषि और तकनीकी क्षेत्रों में। इज़राइल ने भारत को सूचनाएं और सहायता देने के कई गुप्त प्रयास किए, विशेषकर 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान। इस अवधि को "मौन संबंधों" का काल कहा जा सकता है, जहाँ सहयोग तो था, परंतु वह सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया गया।[3] भारत की जनता और राजनीतिक नेतृत्व में इज़राइल को लेकर मिश्रित भावनाएँ थीं—जहाँ एक ओर सुरक्षा और तकनीकी सहयोग की आवश्यकता थी, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के साथ नैतिक प्रतिबद्धता भी बनी हुई थी। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विघटन, और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ भारत की विदेश नीति में लचीलापन आया। फलतः 1992 में भारत ने इज़राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिससे संबंधों के नए युग की शुरुआत हुई।

राजनयिक संबंधों की स्थापना (1992 के बाद)

1992 में भारत और इज़राइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना एक ऐतिहासिक मोड़ था, जिसने दोनों देशों को परस्पर सहयोग के लिए नए द्वार खोलने का अवसर प्रदान किया। यह वह समय था जब भारत आर्थिक उदारीकरण की राह पर अग्रसर था, और शीत युद्ध के बाद वैश्विक राजनीति में भी बदलाव आ चुका था। भारत की विदेश नीति में अब अधिक यथार्थवाद और व्यावहारिकता दिखाई देने लगी थी। राजनयिक संबंधों की औपचारिक शुरुआत के साथ ही दोनों देशों ने अपने-अपने दूतावास नई दिल्ली और तेल अवीव में स्थापित किए। इन दूतावासों ने केवल राजनयिक संचार के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित करने के सेतु के रूप में कार्य किया।[4] शिक्षा,

कृषि, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान हुआ। इस नई कूटनीतिक ऊर्जा के तहत भारत और इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर भी आपसी सहयोग को प्रोत्साहित किया। यद्यपि भारत अब भी फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता रहा, परंतु वह इज़राइल के साथ अपने संबंधों को सार्वजनिक रूप से प्रगाढ़ करता गया। इज़राइल ने भारत के साथ संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" के रूप में देखा, जबकि भारत ने इसे "कार्यात्मक सहयोग" के रूप में संतुलित करने का प्रयास किया। इस संतुलन की नीति ने भारत को पश्चिम एशिया में अपने हितों की रक्षा करते हुए इज़राइल के साथ प्रगाढ़ संबंध विकसित करने में सक्षम बनाया। 1992 के बाद की यह अवधि दोनों देशों के लिए कूटनीतिक दृष्टि से निर्णायक सिद्ध हुई, जिससे भविष्य के व्यापक सहयोग की नींव रखी गई।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग

भारत और इज़राइल के द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा है। 1992 में कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के बाद से इज़राइल भारत का एक प्रमुख रक्षा साझेदार बन गया है। भारत ने इज़राइल से अनेक उन्नत हथियार प्रणालियाँ, रडार, ड्रोन, मिसाइल और निगरानी उपकरण खरीदे हैं। इनमें बराक-8 मिसाइल सिस्टम, स्पाइक एंटी-टैंक मिसाइल, हेरॉन और सर्चर ड्रोन, तथा उन्नत निगरानी रडार प्रमुख हैं। इज़राइल की सैन्य तकनीक उन्नत, भरोसेमंद और भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल रही है। इस कारण भारत की सेनाओं – विशेष रूप से वायु और थल सेना – में इज़राइली उपकरणों का व्यापक उपयोग हुआ है। इसके साथ ही दोनों देशों ने कई रक्षा परियोजनाओं पर मिलकर काम भी किया है, जिससे 'मेक इन इंडिया' पहल को भी प्रोत्साहन मिला है। खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और आतंकवाद-रोधी अभियानों में इज़राइल ने भारत के साथ गहरा सहयोग किया है। 26/11 के मुंबई हमलों के बाद भारत और इज़राइल के बीच खुफिया सहयोग और भी मजबूत हुआ। इज़राइल की खुफिया एजेंसी 'मोसाद' और भारत की 'रॉ' व 'आईबी' के बीच कई संयुक्त प्रयास हुए हैं, जिससे आतंकवाद की रोकथाम में मदद मिली है।[5] दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी प्रारंभ किए हैं, जिनमें विशेष बलों के प्रशिक्षण, शहरी युद्ध की तकनीक, और काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन शामिल हैं। इज़राइल की उच्च तकनीकी क्षमताएँ और भारत की व्यापक सैन्य संरचना – दोनों एक-दूसरे के पूरक बनते हैं। इस रक्षा सहयोग ने भारत की रणनीतिक क्षमताओं को सशक्त करने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास को भी गहराया है। यह संबंध भविष्य में और अधिक सामरिक साझेदारी की दिशा में बढ़ने की संभावना रखता है।

कृषि, जल और नवाचार में सहयोग

भारत और इज़राइल के संबंधों का एक और अत्यंत प्रभावशाली क्षेत्र है – कृषि, जल संसाधन प्रबंधन और नवाचार। इज़राइल ने अत्यंत सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद कृषि और जल तकनीक में वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाई है। इन तकनीकों का उपयोग भारत जैसे विशाल, विविध और कृषि-प्रधान देश के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इज़राइल की कृषि तकनीक जैसे ड्रिप इरिगेशन, नियंत्रित वातावरण में खेती (ग्रीनहाउस), और उन्नत बीज प्रौद्योगिकी को भारत में अपनाया गया है। भारत के विभिन्न राज्यों में भारत-इज़राइल कृषि सहयोग केंद्र (Centers of Excellence) की स्थापना की गई है, जो किसानों को प्रशिक्षण, नवीन तकनीक, और प्रदर्शन परियोजनाओं के माध्यम से सक्षम बना रहे हैं।[6] जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग उल्लेखनीय है। इज़राइल की जल पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन और सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई की तकनीक ने भारत के लिए नई संभावनाएँ खोली हैं। विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जल-संकटग्रस्त राज्यों में इज़राइली तकनीक ने जल की उपलब्धता और उपयोग में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। तकनीकी नवाचार और स्टार्ट-अप संस्कृति में इज़राइल को "स्टार्ट-अप नेशन" के रूप में जाना जाता है। भारत की 'स्टार्टअप इंडिया' योजना के तहत इज़राइल के साथ कई संयुक्त कार्यक्रम, शोध सहयोग, और नवाचार मंचों की शुरुआत हुई है। दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, एग्रो-टेक्नोलॉजी, और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। इस प्रकार, कृषि, जल और नवाचार का यह त्रिकोणीय सहयोग न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता की दृष्टि से भी दोनों देशों के लिए अत्यंत उपयोगी और भविष्य-प्रदर्शक बनता जा रहा है।

International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)
Volume: 09 Issue: 07 | July - 2025 SJIF Rating: 8.586 ISSN: 2582-3930

आर्थिक और व्यापारिक संबंध

भारत और इज़राइल के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध 1992 में कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के बाद निरंतर प्रगति करते रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1992 में मात्र 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2020 के दशक तक बढ़कर 6–7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। यह प्रगति इस बात को दर्शाती है कि दोनों देशों ने अपने व्यापारिक संबंधों को विविध और व्यापक बनाने का प्रयास किया है। प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं में भारत से इज़राइल को रत्न और आभूषण, कृषि उत्पाद, कपड़ा, और औषधियाँ निर्यात की जाती हैं, जबकि इज़राइल से भारत में रक्षा उपकरण, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जल प्रौद्योगिकी और रसायन निर्यात होते हैं। इस बढ़ते व्यापार को और सुदृढ़ करने के लिए भारत और इज़राइल के बीच एक **मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement - FTA)** की दिशा में वार्ताएँ कई वर्षों से चल रही हैं। यदि यह समझौता संपन्न होता है, तो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।[7] निवेश के क्षेत्र में भी दोनों देश सक्रिय रूप से जुड़े हैं। इज़राइली कंपनियाँ भारत में कृषि, जल, साइबर सुरक्षा, और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं, जबकि भारतीय कंपनियाँ इज़राइल की स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों में रुचि दिखा रही हैं। दोनों देशों ने संयुक्त उद्यम और टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन की व्यवस्था शुरू की है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार, भारत-इज़राइल आर्थिक संबंध केवल व्यापार तक सीमित न होकर नवाचार, उद्यमिता और दीर्घकालिक निवेश साझेदारी के रूप में विकसित हो रहे हैं, जो भविष्य में और भी विस्तृत और सशक्त हो सकते हैं।

राजनयिक और राजनीतिक सहयोग

भारत-इज़राइल संबंधों में राजनीतिक और राजनयिक स्तर पर सहयोग ने एक नई ऊँचाई प्राप्त की है, विशेषकर 2014 के बाद जब भारत में नेतृत्व में परिवर्तन आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़राइल के साथ संबंधों को सार्वजनिक रूप से प्राथमिकता दी। मोदी 2017 में इज़राइल की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, जो दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2018 में भारत का दौरा किया। इन उच्च स्तरीय दौरों से राजनीतिक विश्वास, रणनीतिक साझेदारी और पारस्परिक सहयोग को नई दिशा मिली। इन दौरों के दौरान रक्षा, कृषि, जल, साइबर सुरक्षा, नवाचार, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अनेक समझौते संपन्न हुए। राजनीतिक नेतृत्व की यह पारदर्शिता और खुलापन द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुई है।[8] पश्चिम एशिया में भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू 'संतुलन नीति' है। भारत, एक ओर जहाँ इज़राइल के साथ प्रगाढ़ संबंध बना रहा है, वहीं दूसरी ओर वह अरब देशों, विशेषकर खाड़ी देशों के साथ भी व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत बनाए हुए है। भारत ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद में वह फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता रहे, जिससे पश्चिम एशिया में भारत की स्वीकार्यता बनी रहे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर भी भारत और इज़राइल ने समय-समय पर एक-दूसरे का समर्थन किया है। विशेषकर साइबर सुरक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध रणनीतियों, और विज्ञान-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों ने संयुक्त कार्ययोजनाओं पर कार्य किया है। इस तरह, भारत-इज़राइल के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध, केवल रणनीतिक हितों तक सीमित न रहकर, दीर्घकालिक वैश्विक साझेदारी के रूप में सामने आए हैं, जो विश्व राजनीति में भारत की भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं।

भारत-इज़राइल संबंधों की चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

भारत-इज़राइल संबंधों ने पिछले तीन दशकों में अभूतपूर्व प्रगति की है, किंतु इन संबंधों के साथ कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और आलोचनाएँ भी जुड़ी हुई हैं, जो कूटनीतिक रणनीतियों के संतुलन को जटिल बनाती हैं। सबसे प्रमुख चुनौती **फिलिस्तीन मुद्दा** है।[9] भारत ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक के विचारों में यह प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई देती है। भारत हमेशा से यह मानता रहा है कि फिलिस्तीनियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिकार है, और इस दृष्टिकोण ने दशकों तक भारत की पश्चिम एशिया नीति को आकार दिया है। किंतु इज़राइल के साथ संबंधों के सार्वजनिक सुदृढ़ीकरण से यह शंका उत्पन्न हुई है कि भारत की परंपरागत फिलिस्तीन नीति कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रही।

दूसरी चुनौती है **पश्चिम एशिया के अन्य देशों के साथ संतुलन बनाए रखना**। भारत के खाड़ी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। लाखों भारतीय प्रवासी खाड़ी देशों में कार्यरत हैं, और भारत को ऊर्जा की एक बड़ी आपूर्ति इन्हीं

देशों से प्राप्त होती है। इस परिप्रेक्ष्य में इज़राइल के साथ बढ़ती निकटता कभी-कभी अरब देशों की असहमति को जन्म देती है। भारत को अपनी कूटनीतिक चालें इस तरह से चलनी पड़ती हैं कि वह किसी भी पक्ष को नाराज़ न करे और संतुलन बना रहे।

तीसरी चुनौती **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं** के रूप में सामने आती है। देश के भीतर कुछ राजनीतिक और सामाजिक वर्ग यह मानते हैं कि इज़राइल के साथ बढ़ता सहयोग भारत की परंपरागत गुटनिरपेक्ष नीति और नैतिक विदेश नीति के विरुद्ध है। विशेष रूप से वामपंथी और मानवाधिकार समर्थक समूह इज़राइल की फिलिस्तीन नीति की आलोचना करते हुए भारत-इज़राइल सहयोग पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।[10]

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को कभी-कभी आलोचना का सामना करना पड़ता है, विशेषकर उन वैश्विक मंचों पर जहाँ फिलिस्तीन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति अधिक है। भारत की इज़राइल के साथ रक्षा और खुफिया सहयोग को लेकर भी कई बार यह संदेह उठता है कि कहीं यह सहयोग भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित न करे।

इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारत ने अब तक सफलतापूर्वक **नीतिगत संतुलन** बनाए रखा है। उसने फिलिस्तीन के पक्ष में समर्थन व्यक्त करते हुए भी इज़राइल के साथ रक्षा, विज्ञान, कृषि और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया है। अतः भारत-इज़राइल संबंधों की मजबूती का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि भारत किस प्रकार अपने नैतिक आदर्शों और व्यावहारिक कूटनीति के बीच संतुलन स्थापित करता है, और वैश्विक मंचों पर अपनी साख को बनाए रखता है। यह संतुलन ही इस द्विपक्षीय संबंध को स्थायित्व और विश्वसनीयता प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

भारत-इज़राइल संबंधों की यात्रा एक दीर्घकालिक और बहुपरतीय विकास का उदाहरण है, जिसमें दोनों देशों ने समय, आवश्यकता और वैश्विक राजनीति की परिस्थितियों के अनुसार अपने संबंधों को न केवल स्थिर किया, बल्कि उन्हें लगातार विस्तारित भी किया। 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद, इन संबंधों ने रक्षा, कृषि, विज्ञान, जल प्रबंधन, व्यापार, और नवाचार जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय गहराई प्राप्त की है। वर्तमान परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि भारत-इज़राइल संबंध अब केवल रणनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास साझेदारी की दिशा में अग्रसर हैं। यह संबंध पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर जन-जन तक पहुँचने वाले सहयोग में बदल चुका है, जिसमें शिक्षा, स्टार्टअप, तकनीकी नवाचार और आपदा प्रबंधन जैसे मानव-केंद्रित क्षेत्र शामिल हैं। भविष्य में इन संबंधों में और भी संभावनाएँ निहित हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर नवाचार आधारित सहयोग की नींव रख सकते हैं। साथ ही, भारतीय राज्यों और इज़राइली तकनीकी संस्थानों के बीच प्रत्यक्ष भागीदारी को और बढ़ाया जा सकता है। भारत की बहुपक्षीय कूटनीति में इज़राइल की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनती जा रही है। एक ओर भारत पश्चिम एशिया के अरब देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है, तो दूसरी ओर वह इज़राइल के साथ अपनी रणनीतिक और तकनीकी साझेदारी को और गहरा करता है। यह संतुलन भारत की वैश्विक भूमिका को संतुलित, व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है।

अंततः, भारत-इज़राइल संबंधों की यह परिपक्वता इस बात का संकेत देती है कि दोनों देश साझा मूल्यों—जैसे लोकतंत्र, नवाचार, और आत्मनिर्भरता—के आधार पर भविष्य में एक और भी गहरे और स्थायी द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में अग्रसर रहेंगे।

संदर्भ सूची (Reference List)

1. **Kumaraswamy, P. R.** (2010). *India's Israel Policy*. Columbia University Press. [P- 78]
2. **बंसल, अलीना**। (2006)। *भारत-इज़राइल संबंध: विकसित होती दृष्टियाँ* जर्नल ऑफ पीस स्टडीज़। [P- 82]
3. **वही**
4. **Ghosh, Ajay**. (2017). *India’s Foreign Policy: Retrospect and Prospect*. Manohar Publishers. [P -112]

5. **चिब्बर, बीना**। (2018)। *भारत की पश्चिम एशिया नीति: खाड़ी और इज़राइल में संतुलन*। वर्ल्ड अफेयर्स जर्नल। [P-105]
6. **Singh, Surabhi**. (2019). *India and Israel: Strengthening Strategic Ties*. Observer Research Foundation (ORF).
7. **रेड्डी, अनुजा**। (2021)। *मोदी युग में भारत-इज़राइल संबंध*। इंडिया क्वार्टरली, सेज पब्लिकेशन। [P-74]
8. **वही**
9. **Pant, Harsh V.** (2018). *India-Israel Partnership: Convergence and Constraints*. Strategic Analysis, IDSA. [P-39]
10. **जैकब, हप्पीमोन**। (2018)। *भारत और इज़राइल: रक्षा सहयोग से आगे*। ब्रुकिंग्स इंडिया रिपोर्ट।